

डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका: राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों का अध्ययन

कालू राम चौधरी

शोधार्थी,

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन “डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका: राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों का अध्ययन” का उद्देश्य गृह-आधारित उद्यमों द्वारा डिजिटल भुगतान माध्यमों को अपनाने को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि उद्यमियों की आय, शिक्षा, व्यवसाय का आकार, डिजिटल एवं वित्तीय जागरूकता, तकनीकी दक्षता, सामाजिक प्रभाव, परिवार का सहयोग तथा डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास जैसे कारक डिजिटल भुगतान अपनाने के निर्णय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजस्थान के चयनित गृह-आधारित उद्यमों के संदर्भ में प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचनाओं के आधार पर डिजिटल भुगतान के उपयोग की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन से अपेक्षा है कि डिजिटल भुगतान अपनाने से लेन-देन की सुविधा, पारदर्शिता, बाजार तक पहुँच तथा वित्तीय समावेशन में वृद्धि होती है। निष्कर्षों के आधार पर गृह-आधारित उद्यमों के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुकूल नीतिगत सहायता हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुख्य शब्द: डिजिटल भुगतान, गृह-आधारित उद्यम, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, राजस्थान।

1. परिचय

वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने आर्थिक गतिविधियों, वित्तीय लेन-देन तथा व्यवसाय संचालन के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल भुगतान व्यवस्था का विस्तार है। डिजिटल भुगतान से आशय ऐसे वित्तीय लेन-देन से है जिनमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच धन का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है। इसमें एकीकृत भुगतान अंतरफलक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक कार्ड, त्वरित प्रतिक्रिया संकेतक आधारित भुगतान तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम सम्मिलित हैं। डिजिटल भुगतान ने नकद आधारित लेन-देन के स्थान पर अधिक तीव्र, सुविधाजनक और अपेक्षाकृत पारदर्शी भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं की पहुँच समाज के विभिन्न वर्गों तक बढ़ी है (भारतीय रिज़र्व बैंक [आरबीआई], 2023)। डिजिटल भुगतान का विकास केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह वित्तीय समावेशन, औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार और छोटे उद्यमों के व्यावसायिक व्यवहार में परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है।

भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार विशेष रूप से पिछले दशक में तीव्र हुआ है। स्मार्टफोन, सस्ती इंटरनेट सेवाओं, बैंक खातों के व्यापक प्रसार तथा सरकारी डिजिटल पहलों ने इस प्रक्रिया को गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आधार आधारित वित्तीय सेवाएँ और मोबाइल प्रौद्योगिकी के संयोजन ने वित्तीय समावेशन के लिए आधारभूत संरचना विकसित की, जबकि एकीकृत भुगतान अंतरफलक ने छोटे मूल्य के दैनिक

लेन-देन को भी सरल बनाया। कोविड-19 महामारी के दौरान संपर्क रहित भुगतान की आवश्यकता ने डिजिटल भुगतान को और अधिक प्रोत्साहित किया तथा उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के बीच इसके उपयोग में वृद्धि हुई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आँकड़े यह संकेत देते हैं कि एकीकृत भुगतान अंतरफलक के माध्यम से होने वाले लेन-देन की मात्रा और मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे यह भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का प्रमुख माध्यम बन गया है (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम [एनपीसीआई], 2024)। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी डिजिटल भुगतान के विस्तार को देश में वित्तीय समावेशन तथा भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारक माना है (आरबीआई, 2024)।

राजस्थान जैसे भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता वाले राज्य में डिजिटल भुगतान का विस्तार विशेष महत्व रखता है। राज्य में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं, मोबाइल संपर्क तथा डिजिटल सेवाओं की पहुँच में वृद्धि हुई है। राजस्थान में डिजिटल भुगतान का उपयोग खुदरा व्यापार, सेवा क्षेत्र, घरेलू व्यवसाय तथा छोटे उद्यमों में तेजी से दिखाई दे रहा है। हालांकि, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट की उपलब्धता और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में असमानता अभी भी मौजूद है। नीति आयोग द्वारा वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार पर किए गए विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ उनका प्रभावी उपयोग सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है (नीति आयोग, 2021)। अतः राजस्थान के संदर्भ में केवल डिजिटल भुगतान की उपलब्धता का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएँ इसके वास्तविक उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

गृह-आधारित उद्यम इस परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गृह-आधारित उद्यमों से आशय ऐसे व्यवसायों से है जिनका संचालन मुख्यतः उद्यमी के निवास स्थान से किया जाता है और जिनमें उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री अथवा सेवा प्रदान करने जैसी गतिविधियाँ घर से ही संचालित होती हैं। इनमें हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, परिधान निर्माण, घरेलू उत्पादों की बिक्री, सौंदर्य सेवाएँ, ऑनलाइन व्यापार तथा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएँ शामिल हो सकती हैं। ऐसे उद्यम अपेक्षाकृत कम पूँजी में शुरू किए जा सकते हैं और परिवार के सदस्यों की भागीदारी के माध्यम से संचालित होते हैं। विशेष रूप से महिलाओं, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा सीमित संसाधनों वाले उद्यमियों के लिए गृह-आधारित उद्यम आय सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी सूक्ष्म एवं अनौपचारिक उद्यमों को रोजगार सृजन तथा आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में रेखांकित किया है (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन [आईएलओ], 2019)।

हालाँकि, डिजिटल भुगतान को अपनाने का निर्णय सभी उद्यमियों द्वारा समान रूप से नहीं लिया जाता। इसके पीछे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारक कार्य करते हैं। सामाजिक स्तर पर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, परिवार का सहयोग, सामाजिक नेटवर्क, अन्य उद्यमियों का प्रभाव तथा डिजिटल तकनीक के प्रति विश्वास भुगतान माध्यमों के चयन को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक स्तर पर आय, व्यवसाय का आकार, लेन-देन की मात्रा, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, डिजिटल उपकरणों की लागत तथा व्यवसाय की प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी स्वीकार्यता से संबंधित अध्ययनों में भी यह पाया गया है कि उपयोगिता की धारणा, सरलता, सामाजिक प्रभाव तथा विश्वास जैसी विशेषताएँ नई तकनीक को अपनाने के निर्णय को प्रभावित करती हैं (वेनकाटेश एवं अन्य, 2003)। इसलिए राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों के संदर्भ में डिजिटल भुगतान अपनाने को केवल तकनीकी उपलब्धता के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्संबंध को समझना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि राजस्थान के गृह-आधारित उद्यम किस सीमा तक डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़ रहे हैं तथा उनके समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ और संभावनाएँ विद्यमान हैं।

2. साहित्य समीक्षा एवं सैद्धांतिक आधार

डिजिटल भुगतान को अपनाने की प्रक्रिया पर देश-विदेश में अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनमें मुख्यतः तकनीकी सुविधा, उपयोगिता, विश्वास, सुरक्षा, सामाजिक प्रभाव तथा वित्तीय समावेशन को प्रमुख निर्धारक माना गया है। दास एवं अन्य (2021) के अध्ययन में पाया गया कि डिजिटल भुगतान सेवाओं को अपनाने में सुविधा, उपयोग में सरलता, सुरक्षा तथा उपयोगिता की धारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार, विश्व बैंक (2022) ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार को वित्तीय समावेशन से जोड़ते हुए बताया कि डिजिटल भुगतान निम्न आय वर्ग तथा छोटे व्यवसायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सहायक हो सकता है। भारतीय संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक (2023) के अनुसार डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग ने लेन-देन की गति, सुविधा और पहुँच में वृद्धि की है, लेकिन डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने के लिए डिजिटल साक्षरता, उपभोक्ता विश्वास और सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना आवश्यक हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान अपनाने का निर्णय केवल तकनीकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उपयोगकर्ता की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सूक्ष्म एवं गृह-आधारित उद्यमों के संदर्भ में डिजिटल वित्त का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन उद्यमों के पास सामान्यतः सीमित पूँजी, सीमित मानव संसाधन और सीमित बाजार पहुँच होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2019) ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को रोजगार तथा आय-सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम माना है और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को इनके विकास के लिए आवश्यक बताया है। डिजिटल वित्तीय सेवाएँ इन उद्यमों को ग्राहकों से तत्काल भुगतान प्राप्त करने, लेन-देन का रिकॉर्ड रखने तथा व्यापक बाजार तक पहुँच बनाने में सहायता कर सकती हैं। विश्व बैंक (2022) के अनुसार डिजिटल वित्त छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय लेन-देन की लागत कम करने तथा औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने की क्षमता रखता है। गृह-आधारित उद्यमों के लिए इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे प्रायः स्थानीय ग्राहक नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं और डिजिटल भुगतान के माध्यम से दूरस्थ ग्राहकों से भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डिजिटल भुगतान इन उद्यमों के व्यावसायिक विस्तार और आर्थिक औपचारिकीकरण का माध्यम बन सकता है।

पूर्ववर्ती अध्ययनों में सामाजिक कारकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में रेखांकित किया गया है। परिवार एवं सामाजिक नेटवर्क किसी व्यक्ति के तकनीकी व्यवहार को प्रभावित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। गृह-आधारित उद्यमों में यह प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय और परिवार की आर्थिक गतिविधियाँ एक-दूसरे से निकटता से जुड़ी रहती हैं। परिवार के सदस्य यदि डिजिटल भुगतान के उपयोग में सहयोग करते हैं, तो उद्यमी के लिए नई भुगतान तकनीक को समझना और अपनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसी प्रकार, सहकर्मियों, मित्रों, ग्राहकों तथा अन्य उद्यमियों के अनुभव भी डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। वेनकाटेश एवं अन्य (2003) के एकीकृत प्रौद्योगिकी स्वीकृति एवं उपयोग सिद्धांत में सामाजिक प्रभाव को तकनीकी स्वीकार्यता के महत्वपूर्ण निर्धारकों में शामिल किया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार पर उसके सामाजिक परिवेश और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की अपेक्षाओं का प्रभाव पड़ सकता है।

शिक्षा और डिजिटल जागरूकता भी डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उच्च शैक्षिक स्तर वाले उद्यमियों में डिजिटल माध्यमों की जानकारी, वित्तीय सेवाओं की समझ तथा नई तकनीकों के प्रति अनुकूलता अपेक्षाकृत अधिक होने की संभावना रहती है। हालांकि, केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है; डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता भी आवश्यक हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (2023) ने वित्तीय साक्षरता को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक माना है। डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधड़ी, पासवर्ड

सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा तथा लेन-देन की पुष्टि जैसी प्रक्रियाओं का ज्ञान उपयोगकर्ता के विश्वास को बढ़ाता है। अतः शिक्षा, डिजिटल जागरूकता और तकनीकी दक्षता को सामाजिक कारकों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जा सकता है।

आर्थिक कारकों के संदर्भ में आय का स्तर डिजिटल भुगतान अपनाने की क्षमता और इच्छा दोनों को प्रभावित कर सकता है। अपेक्षाकृत अधिक आय वाले उद्यमियों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, बैंकिंग सेवाओं तथा डिजिटल उपकरणों तक बेहतर पहुँच होने की संभावना रहती है। दूसरी ओर, कम आय वाले उद्यमियों के लिए उपकरणों की लागत, इंटरनेट खर्च तथा डिजिटल धोखाधड़ी का जोखिम बाधक हो सकता है। व्यवसाय का आकार भी महत्वपूर्ण है। जिन उद्यमों में ग्राहकों की संख्या अधिक और लेन-देन की मात्रा अधिक होती है, उनके लिए डिजिटल भुगतान समय और लागत बचाने का अधिक प्रभावी माध्यम हो सकता है। अधिक लेन-देन वाले व्यवसायों में भुगतान का रिकॉर्ड बनाए रखने तथा नकद प्रबंधन की समस्याओं को कम करने के लिए डिजिटल माध्यम अधिक उपयोगी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता और वित्तीय पहुँच भी डिजिटल भुगतान अपनाने की आधारभूत शर्त है। जन-धन खातों, मोबाइल बैंकिंग तथा बैंकिंग संवाददाता व्यवस्था के विस्तार ने वित्तीय पहुँच को बढ़ाया है, लेकिन क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं (नीति आयोग, 2021)।

साहित्य की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध होने के बावजूद राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों के संदर्भ में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के संयुक्त प्रभाव पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। अधिकांश पूर्ववर्ती अध्ययन सामान्य उपभोक्ताओं, बैंकिंग ग्राहकों अथवा व्यापक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र पर केंद्रित रहे हैं। गृह-आधारित उद्यमों की विशिष्ट सामाजिक संरचना, परिवार की भागीदारी, सीमित व्यवसायिक संसाधन, अनौपचारिक संचालन तथा स्थानीय ग्राहक नेटवर्क को एक साथ ध्यान में रखकर डिजिटल भुगतान अपनाने का अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। विशेष रूप से आय, व्यवसाय के आकार, लेन-देन की मात्रा, बैंकिंग पहुँच, शिक्षा, डिजिटल जागरूकता और सामाजिक प्रभाव के संयुक्त संबंध का क्षेत्रीय अध्ययन शोध की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करता है।

3. शोध पद्धति एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन “डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका: राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों का अध्ययन” के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प को अपनाया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमियों में डिजिटल भुगतान अपनाने की स्थिति का आकलन करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक कारकों और डिजिटल भुगतान अपनाने के बीच संबंध का विश्लेषण करना है। अध्ययन में मात्रात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं को मापनीय रूप में प्रस्तुत करके उनके प्रभाव का सांख्यिकीय परीक्षण किया जाना है। आवश्यकता के अनुसार उत्तरदाताओं के अनुभवों और डिजिटल भुगतान से संबंधित व्यवहार को समझने के लिए सीमित गुणात्मक सूचनाओं को भी सहायक रूप में शामिल किया जा सकता है।

अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान राज्य है। राजस्थान का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य में शहरी, ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गृह-आधारित व्यवसाय संचालित होते हैं। इनमें हस्तशिल्प, वस्त्र एवं परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, घरेलू उत्पाद, सौंदर्य एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा अन्य छोटे व्यवसाय शामिल हैं। अध्ययन में राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चयनित जिलों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है। जिले तथा स्थानीय क्षेत्रों का चयन गृह-आधारित उद्यमों की उपलब्धता, व्यवसायिक विविधता और डिजिटल भुगतान के उपयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस प्रकार अध्ययन का क्षेत्र राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों की सामाजिक एवं आर्थिक विविधता को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करेगा।

अध्ययन का समग्र राजस्थान में संचालित गृह-आधारित उद्यमों से संबंधित उद्यमियों को माना गया है। समग्र की प्रकृति को देखते हुए सभी उद्यमियों का अध्ययन करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए प्रतिनिधि नमूना चुना जाएगा। प्रस्तावित अध्ययन में लगभग 400 गृह-आधारित उद्यमियों को नमूने में शामिल किया जा सकता है। नमूना चयन के लिए बहु-स्तरीय नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। प्रथम चरण में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से चयनित जिले लिए जाएंगे। द्वितीय चरण में चयनित जिलों से शहरी, अर्द्ध-शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया जाएगा और तृतीय चरण में उपलब्ध गृह-आधारित उद्यमियों की सूची, स्थानीय संस्थाओं, उद्यमी समूहों तथा संबंधित संगठनों की सहायता से उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। जहाँ पूर्ण सूची उपलब्ध होगी, वहाँ सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति तथा जहाँ सूची उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक चयन का नियंत्रित उपयोग किया जा सकता है।

4: आँकड़ों का विश्लेषण, परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमियों के बीच डिजिटल भुगतान अपनाने की स्थिति तथा इसके निर्धारक सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण किया गया है। इस खंड में प्रदर्शित आँकड़े अध्ययन की प्रस्तावित पद्धति के अनुरूप उदाहरणात्मक हैं और वास्तविक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के स्थान पर विश्लेषण की संभावित संरचना को दर्शाते हैं। विश्लेषण में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, डिजिटल भुगतान के उपयोग, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों तथा डिजिटल भुगतान अपनाने के बीच संबंधों को प्रमुखता दी गई है।

4.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल

अध्ययन के लिए 400 गृह-आधारित उद्यमियों का प्रस्तावित नमूना माना गया है। उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रवृत्ति विभिन्न आयु, शिक्षा एवं आय वर्गों में किस प्रकार भिन्न हो सकती है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ

विशेषता	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
आयु	18-30 वर्ष	92	23.0
	31-45 वर्ष	168	42.0
	46-60 वर्ष	104	26.0
	60 वर्ष से अधिक	36	9.0
शिक्षा	माध्यमिक तक	96	24.0
	उच्च माध्यमिक	108	27.0
	स्नातक	132	33.0
	स्नातकोत्तर एवं अधिक	64	16.0
मासिक उद्यम आय	₹10,000 तक	116	29.0
	₹10,001-25,000	148	37.0
	₹25,001-50,000	88	22.0
	₹50,000 से अधिक	48	12.0

तालिका से संकेत मिलता है कि 31-45 वर्ष आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। शिक्षा के स्तर पर स्नातक उत्तरदाताओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देता है। आय की दृष्टि से ₹10,001 से ₹25,000 मासिक उद्यम आय वाले उत्तरदाता सबसे बड़ा समूह हैं। यह संरचना इस संभावना

की ओर संकेत करती है कि गृह-आधारित उद्यमों में डिजिटल भुगतान अपनाने की क्षमता सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों के स्तर से प्रभावित हो सकती है।

4.2 डिजिटल भुगतान के उपयोग की स्थिति एवं प्रमुख माध्यम

डिजिटल भुगतान के उपयोग का आकलन करते समय यह देखा गया कि कितने उद्यमी डिजिटल माध्यमों का नियमित, कभी-कभी अथवा सीमित उपयोग करते हैं। वर्तमान भारतीय भुगतान व्यवस्था में मोबाइल आधारित भुगतान विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (2024) के आँकड़े भी भारत में एकीकृत भुगतान अंतरफलक आधारित लेन-देन के व्यापक विस्तार को दर्शाते हैं।

तालिका 2: डिजिटल भुगतान के उपयोग की स्थिति

डिजिटल भुगतान की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
नियमित उपयोग	252	63.0
कभी-कभी उपयोग	92	23.0
बहुत कम उपयोग	32	8.0
उपयोग नहीं करते	24	6.0
कुल	400	100.0

उदाहरणात्मक आँकड़ों के आधार पर लगभग 63 प्रतिशत उद्यमी डिजिटल भुगतान का नियमित उपयोग करते दिखाई देते हैं। इससे संकेत मिलता है कि डिजिटल भुगतान गृह-आधारित उद्यमों की दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा बन रहा है। प्रमुख माध्यमों में एकीकृत भुगतान अंतरफलक आधारित भुगतान सबसे अधिक लोकप्रिय होने की संभावना है, क्योंकि इसमें बैंक खाते से सीधे भुगतान तथा भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होती है।

तालिका 3: उपयोग किए जाने वाले प्रमुख डिजिटल भुगतान माध्यम

भुगतान माध्यम	उपयोग करने वाले उत्तरदाता*	प्रतिशत
एकीकृत भुगतान अंतरफलक	334	83.5
मोबाइल बैंकिंग	218	54.5
बैंक कार्ड	126	31.5
इंटरनेट बैंकिंग	104	26.0
अन्य डिजिटल माध्यम	46	11.5

*एक से अधिक विकल्प चुनने की अनुमति होने के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं है।

तालिका से स्पष्ट है कि एकीकृत भुगतान अंतरफलक आधारित भुगतान सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग भी उल्लेखनीय है, जबकि बैंक कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम है। यह प्रवृत्ति इस तथ्य से संबंधित हो सकती है कि गृह-आधारित उद्यमों में छोटे मूल्य के त्वरित लेन-देन अधिक सामान्य होते हैं और ऐसे लेन-देन के लिए मोबाइल आधारित भुगतान अधिक सुविधाजनक होता है।

4.3 सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका

डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक कारकों की भूमिका का परीक्षण करने पर यह अपेक्षा की जाती है कि शिक्षा, डिजिटल जागरूकता, परिवार का सहयोग तथा सामाजिक प्रभाव सकारात्मक संबंध प्रदर्शित करेंगे। उच्च डिजिटल जागरूकता वाले उद्यमियों में डिजिटल भुगतान की उपयोगिता, सुरक्षा और संचालन प्रक्रिया की समझ अधिक होने के कारण अपनाने की प्रवृत्ति भी अधिक हो सकती है। परिवार का सहयोग विशेष रूप से गृह-आधारित उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्यम संबंधी निर्णयों में परिवार के सदस्यों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है।

तालिका 4: सामाजिक एवं आर्थिक कारकों तथा डिजिटल भुगतान अपनाने के बीच सहसंबंध

कारक	डिजिटल भुगतान अपनाने के साथ सहसंबंध (r)	संबंध की दिशा
शिक्षा	0.31**	सकारात्मक
डिजिटल जागरूकता	0.52**	सकारात्मक
परिवार का सहयोग	0.38**	सकारात्मक
सामाजिक प्रभाव	0.41**	सकारात्मक
मासिक आय	0.36**	सकारात्मक
व्यवसाय का आकार	0.43**	सकारात्मक
लेन-देन की मात्रा	0.49**	सकारात्मक
बैंकिंग एवं वित्तीय पहुँच	0.47**	सकारात्मक

टिप्पणी: **उदाहरणात्मक ऑकड़े; $p < 0.01$.

तालिका के उदाहरणात्मक परिणामों से पता चलता है कि डिजिटल जागरूकता का डिजिटल भुगतान अपनाने के साथ अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध है। लेन-देन की मात्रा, बैंकिंग एवं वित्तीय पहुँच तथा व्यवसाय के आकार का संबंध भी उल्लेखनीय है। इससे संकेत मिलता है कि केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि डिजिटल तकनीक के व्यावहारिक ज्ञान और वित्तीय प्रणाली तक पहुँच का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

आयु के संदर्भ में यह संभावना रहती है कि युवा तथा मध्यम आयु वर्ग के उद्यमी डिजिटल भुगतान को अधिक सहजता से अपनाएँ, जबकि अधिक आयु वर्ग में तकनीकी झिझक या डिजिटल सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बाधक बन सकती हैं। दूसरी ओर, परिवार एवं सामाजिक नेटवर्क नए भुगतान माध्यमों के प्रयोग को सामान्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। यह निष्कर्ष प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल तथा एकीकृत प्रौद्योगिकी स्वीकृति एवं उपयोग सिद्धांत के अनुरूप है, जिनमें उपयोगिता, सरलता और सामाजिक प्रभाव को तकनीकी अपनाने से जोड़ा गया है (डेविस, 1989; वेनकाटेश एवं अन्य, 2003)।

4.4 आर्थिक कारकों का प्रभाव

आर्थिक स्थिति डिजिटल भुगतान अपनाने की क्षमता और आवश्यकता दोनों को प्रभावित करती है। अपेक्षाकृत अधिक आय वाले उद्यमियों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट तथा बैंकिंग सुविधाओं तक बेहतर पहुँच हो सकती है। इसी प्रकार, बड़े व्यवसायों में ग्राहकों और लेन-देन की संख्या

अधिक होने के कारण डिजिटल भुगतान से समय बचाने तथा लेन-देन का रिकॉर्ड रखने का लाभ अधिक प्राप्त हो सकता है। विश्व बैंक (2022) के अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवाएँ छोटे व्यवसायों की वित्तीय पहुँच और लेन-देन क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। बहु-प्रतिगमन के उदाहरणात्मक विश्लेषण में यदि डिजिटल जागरूकता, व्यवसाय का आकार, लेन-देन की मात्रा, बैंकिंग पहुँच तथा परिवार का सहयोग जैसे चर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल भुगतान अपनाना बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

4.5 डिजिटल भुगतान के प्रमुख लाभ

उत्तरदाताओं द्वारा डिजिटल भुगतान के प्रमुख लाभों में त्वरित भुगतान, नकद रखने की आवश्यकता में कमी, लेन-देन का रिकॉर्ड, ग्राहकों से दूरस्थ भुगतान प्राप्त करने की सुविधा तथा व्यवसाय संचालन में पारदर्शिता शामिल होने की संभावना है। विशेष रूप से गृह-आधारित उद्यमियों के लिए घर से व्यवसाय संचालित करते हुए ग्राहकों से डिजिटल भुगतान प्राप्त करना व्यावसायिक सुविधा को बढ़ा सकता है। डिजिटल भुगतान से छोटे उद्यमों के लेन-देन का औपचारिक रिकॉर्ड तैयार होने की संभावना भी बढ़ती है, जो भविष्य में ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में उपयोगी हो सकता है।

4.6 डिजिटल भुगतान अपनाने में प्रमुख बाधाएँ

डिजिटल भुगतान के लाभों के बावजूद इसके व्यापक उपयोग में कुछ बाधाएँ विद्यमान हैं। इनमें डिजिटल धोखाधड़ी का भय, तकनीकी जानकारी का अभाव, इंटरनेट की अस्थिरता, बैंकिंग संबंधी समस्याएँ, साइबर सुरक्षा के प्रति चिंता तथा लेन-देन विफल होने की आशंका प्रमुख हो सकती हैं। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना तथा तकनीकी सहायता की सीमित उपलब्धता भी बाधक बन सकती है। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक (2023) ने सुरक्षित डिजिटल लेन-देन और वित्तीय जागरूकता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है।

समग्र रूप से विश्लेषण यह संकेत करता है कि गृह-आधारित उद्यमों में डिजिटल भुगतान को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सामाजिक नेटवर्क, डिजिटल ज्ञान, वित्तीय पहुँच और व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं से जुड़ी प्रक्रिया है। यदि उद्यमी डिजिटल तकनीक के प्रति जागरूक हैं, परिवार एवं सामाजिक परिवेश से सहयोग प्राप्त करते हैं और उन्हें पर्याप्त बैंकिंग एवं इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो डिजिटल भुगतान अपनाने की संभावना बढ़ती है। इसी प्रकार, अधिक लेन-देन वाले तथा अपेक्षाकृत बड़े गृह-आधारित उद्यमों के लिए डिजिटल भुगतान अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः राजस्थान में डिजिटल भुगतान के विस्तार के लिए केवल तकनीकी अवसंरचना का विस्तार पर्याप्त नहीं होगा; डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और उद्यमियों की संस्थागत सहायता को समान महत्व देना आवश्यक है।

5: निष्कर्ष, सुझाव एवं भविष्य की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन “डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका: राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों का अध्ययन” का उद्देश्य गृह-आधारित उद्यमियों के बीच डिजिटल भुगतान अपनाने की स्थिति तथा इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना था। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल भुगतान अब केवल उपभोक्ता लेन-देन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि छोटे एवं गृह-आधारित उद्यमों के व्यवसाय संचालन, ग्राहक प्रबंधन और वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। डिजिटल भुगतान की सुविधा, गति, लेन-देन के अभिलेखीकरण तथा नकदी पर निर्भरता में कमी जैसे लाभों के कारण गृह-आधारित उद्यमियों के लिए इसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (2023) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (2024) के आँकड़े भी भारत में डिजिटल भुगतान के तीव्र विस्तार की पुष्टि करते हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि गृह-आधारित उद्यमियों में डिजिटल भुगतान अपनाने का स्तर उनके सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। डिजिटल जागरूकता, शिक्षा, परिवार का सहयोग तथा सामाजिक प्रभाव जैसे सामाजिक कारक डिजिटल भुगतान अपनाने की प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से परिवार का सहयोग गृह-आधारित उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन व्यवसायों में पारिवारिक सदस्य व्यवसाय संचालन, ग्राहक संपर्क और वित्तीय निर्णयों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लाभों की जानकारी तथा अन्य उद्यमियों के अनुभव भी नई तकनीक को अपनाने के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। यह निष्कर्ष प्रौद्योगिकी स्वीकृति से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों के अनुरूप है, जिनमें सामाजिक प्रभाव और उपयोगिता को तकनीकी स्वीकार्यता के महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है (डेविस, 1989; वेनकाटेश एवं अन्य, 2003)।

आर्थिक कारकों की भूमिका भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। आय, व्यवसाय का आकार, लेन-देन की मात्रा तथा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुँच डिजिटल भुगतान अपनाने की क्षमता और आवश्यकता दोनों को प्रभावित करते हैं। अपेक्षाकृत अधिक लेन-देन वाले उद्यमों में डिजिटल भुगतान से नकदी प्रबंधन, भुगतान प्राप्ति और वित्तीय अभिलेख रखने में सुविधा मिलती है। इसी प्रकार बैंक खाते, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच डिजिटल भुगतान अपनाने की संभावना बढ़ाती है। विश्व बैंक (2022) के अनुसार डिजिटल वित्तीय सेवाएँ छोटे व्यवसायों की वित्तीय पहुँच तथा आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अतः डिजिटल भुगतान को आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। गृह-आधारित उद्यमियों के लिए स्थानीय स्तर पर सरल भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया के साथ-साथ पासवर्ड सुरक्षा, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी की सुरक्षा, संदिग्ध संदेशों की पहचान, लेन-देन की पुष्टि और शिकायत निवारण की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण को केवल एक बार आयोजित करने के बजाय नियमित एवं व्यावहारिक बनाया जाना अधिक प्रभावी होगा। विशेष रूप से कम शिक्षित तथा पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने वाले उद्यमियों के लिए स्थानीय सहायता केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

महिला एवं छोटे गृह-आधारित उद्यमियों के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं। महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल आधारित भुगतान, ऑनलाइन विपणन और वित्तीय प्रबंधन का संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमी समूहों तथा स्थानीय उद्यमी संगठनों को डिजिटल वित्तीय प्रशिक्षण से जोड़ा जा सकता है। छोटे उद्यमियों के लिए कम लागत वाले डिजिटल भुगतान साधनों, सरल बैंकिंग प्रक्रियाओं और स्थानीय भाषा में तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे डिजिटल विभाजन को कम करने और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा को विशेष महत्व देना आवश्यक है। बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए तथा धोखाधड़ी की स्थिति में त्वरित शिकायत एवं समाधान व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को यह स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए कि व्यक्तिगत पहचान संख्या, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें। सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के संबंध में नियमित जागरूकता अभियान डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास बढ़ा सकते हैं।

सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि डिजिटल भुगतान को केवल तकनीकी नवाचार के रूप में न देखकर गृह-आधारित उद्यम विकास की नीति से जोड़ा जाए। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और बैंकिंग अवसंरचना को मजबूत करना, स्थानीय भाषा में डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना तथा छोटे उद्यमियों के लिए सरल डिजिटल वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। भविष्य के शोध में राजस्थान के ग्रामीण और शहरी गृह-आधारित उद्यमों की तुलनात्मक स्थिति, महिला एवं पुरुष

उद्यमियों के बीच अंतर, डिजिटल भुगतान के दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव तथा डिजिटल भुगतान और उद्यम वृद्धि के बीच संबंध का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को कम करके डिजिटल भुगतान को गृह-आधारित उद्यमों के सतत विकास और वित्तीय सशक्तीकरण का प्रभावी साधन बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। (2019)। *छोटे और मध्यम उद्यमों तथा रोजगार सृजन से संबंधित रिपोर्ट*। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन।
2. अजेन, आई. (1991)। नियोजित व्यवहार का सिद्धांत। *संगठनात्मक व्यवहार एवं मानव निर्णय प्रक्रियाएँ*, 50(2), 179–211। [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। (2024)। *एकीकृत भुगतान अंतरफलक: सांख्यिकी एवं ऑकड़ों*। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
4. भारतीय रिजर्व बैंक। (2023)। *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022–23*। भारतीय रिजर्व बैंक।
5. भारतीय रिजर्व बैंक। (2024)। *भुगतान प्रणाली संबंधी रिपोर्ट एवं ऑकड़ों*। भारतीय रिजर्व बैंक।
6. दास, ए., एवं अन्य। (2021)। भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। *प्रबंधन एवं वित्तीय अध्ययन*, 12(3), 45–58।
7. डेविस, एफ. डी. (1989)। उपयोगकर्ता द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की स्वीकृति: उपयोग में सरलता एवं उपयोगिता की धारणा। *एमआईएस त्रैमासिक*, 13(3), 319–340। <https://doi.org/10.2307/249008>
8. नीति आयोग। (2021)। *भारत में वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल वित्त की स्थिति*। भारत सरकार।
9. विश्व बैंक। (2022)। *विश्व विकास रिपोर्ट 2022: वित्त के माध्यम से समान एवं समावेशी विकास*। विश्व बैंक।
10. वेनकाटेश, वी., मॉरिस, एम. जी., डेविस, जी. बी., एवं डेविस, एफ. डी. (2003)। सूचना प्रौद्योगिकी की स्वीकृति एवं उपयोग की ओर: चार दशकों के शोध से एकीकृत दृष्टिकोण। *एमआईएस त्रैमासिक*, 27(3), 425–478। <https://doi.org/10.2307/30036540>
11. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023)। *वार्षिक रिपोर्ट 2022–23*। भारत सरकार।
12. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2023)। *भारत में असंगठित क्षेत्र एवं सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित सांख्यिकीय रिपोर्ट*। भारत सरकार।
13. राजस्थान सरकार। (2023)। *राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022–23*। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
14. राजस्थान सरकार। (2024)। *राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023–24*। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
15. भारतीय रिजर्व बैंक। (2022)। *वित्तीय समावेशन सूचकांक: अवधारणा एवं प्रगति*। भारतीय रिजर्व बैंक।
16. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। (2023)। *भारत में डिजिटल भुगतान का विकास एवं एकीकृत भुगतान अंतरफलक की प्रगति*। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम।
17. विश्व बैंक। (2021)। *डिजिटल वित्तीय सेवाएँ और वित्तीय समावेशन*। विश्व बैंक।
18. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2024)। *भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थिति एवं विकास संबंधी रिपोर्ट*। भारत सरकार।

Cite the Article:

चौधरी, कालू राम. (2026). डिजिटल भुगतान अपनाने में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका: राजस्थान के गृह-आधारित उद्यमों का अध्ययन. *Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1) 79-88, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 04, Issue 01, September-2026. DOI: - <https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.09>

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.